प्रभाकर अडिगा

बनाम

"गौरी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3007-3008/2017)

20 फरवरी, 2017

[अरुण मिश्रा और अमितावा रॉय, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 50 - कानूनी प्रतिनिधि -स्थायी निषेधाज्ञा का हुक्म - विधि विरुद्ध निष्पादन योग्यता निर्णय -देनदार का प्रतिनिधि - आयोजित: निषेधाज्ञा के लिए डिक्री मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है निर्णय-विवाद/या - जब मुकदमा दायर किया गया अधिकार वंशानुगत हो, तो डिक्री आम तौर पर समाप्त नहीं होगी और विधिक प्रतिनिधि द्वारा लागू की जा सकती है।डिक्री-धारक का और फैसले-देनदार या उसके कानूनी के खिलाफ प्रतिनिधि - यह पूछना लोकनीति के विरुद्ध होगा डिक्री धारक कानूनी के खिलाफ एक बार फिर से मुकदमा दायर करने के लिए निर्णय-देनदार के प्रतिनिधि जब कारण और निषेधाज्ञा कायम है

न्यायालय ने अपीलों को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1.1. सी. पी. सी. की धारा 50 स्थायी निषेधाज्ञा सहित सभी प्रकार के फरमानों के निष्पादन से संबंधित है।सी. पी. सी. की धारा 146 में यह प्रावधान है कि जहां कोई भी आवेदन जो किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जा सकता है, वह किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जा सकता है, सिवाय इसके कि संहिता में अन्यथा प्रावधान किया गया है, आदेश 21 नियम 32 निषेधाज्ञा, वैवाहिक

अधिकारों की बहाली और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के निष्पादन का तरीका प्रदान करता है।सी. पी. सी. की धारा 50 जो कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ डिक्री के प्रवर्तन के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है, को आदेश 21 नियम 32 सी. पी. सी. के साथ पढ़ा जाएगा। सी. पी. सी. की धारा 50 (2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 'स्थायी' के लिए एक फरमान निषेधाज्ञा को निर्णय देनदार या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।[पारस 11,12] {731-G-H; 732-A-C}

1.2 तत्काल मामले में मुकदमे में जिस अधिकार पर निर्णय दिया गया था और जो निष्कर्ष विवादित संपत्ति के बारे में निषेधाज्ञा देने के लिए आधार के रूप में दर्ज किए गए हैं, जो वंशानुगत और आंशिक है, वे डिक्री धारकों के कानूनी उत्तराधिकारी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेंगे, बल्कि निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों को भी बाध्य करेंगे।सी. पी. सी. की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि जब कोई निर्णय-देनदार डिक्री के संतुष्ट होने से पहले मर जाता है, तो इसे कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है। धारा 50 किसी विशेष प्रकार की डिक्री तक सीमित नहीं है।निषेधाज्ञा के लिए डिक्री मृतक निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ भी निष्पादित की जा सकती है, उक्ति "एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कैम पर्सन" मामलों के कुछ वर्ग तक सीमित है और जब मुकदमा दायर किया गया अधिकार वंशानुगत है, तो डिक्री आम तौर पर उपशमन करना नहीं होगी और इसे डीरी-धारक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा और निर्णय-देनदार या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। प्रतिनिधि।जब कारण और निषेधाज्ञा बनी रहती है तो डिक्री-धारक को निर्णय-ऋणदाता के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ फिर से मुकदमा करने के लिए कहना सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि निषेधाज्ञा का आदेश आम तौर पर भूमि के साथ नहीं चलता है।वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में में इसे लागू नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, सी. पी. सी. की धारा

50 में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की डिक्री को कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।[पैरा 26] [743-डी-एच]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और निष्पादन अदालत द्वारा जारी निर्देश कि कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा डिक्री का पालन करने के लिए एक वचन दिया जाना उचित है, जिसमें विफल रहने पर निष्पादन अदालत "आदेश XXI नियम 32 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत डिक्री को लागू करने के लिए कानून के अनुसार अनुमेय तरीके से आगे बढ़ेगी। [पैरा 27] [744-ए-बी]

शिवप्पा बसवंतप्पा देवरावर बनाम बाबोजन 1999 (4) कर। आई. जे. 293-अस्वीकृत।

मुथुकरुप्पा पिल्लई और अन्र बनामगणेशन (1995) पूरक 3 एस. सी. सी. 69; रामचंद्र देशपांडे बनाम लक्ष्मण राव कुलकर्णी ए. आई. आर. 2000 कर्नाटक 298; कन्हैया लाल बनाम बाबू राम (मृत) विधिक प्रतिनिधि तथा अन्य , ए एन. आर. (1999) 8 एससीसी 529; जीए वेंकटोप्पा बनाम अंजनाप्पा और अन्य । आईएलआर 2006 कर्नाटक 4456; गिरिजानंदिनी देवी बनाम बीजेंदर नारायण चौधरी ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1124 :1967 एस. सी. आर. 93; डी. सूजा जे. वी. श्री ए. जोसेफ ए. आई. आर. 1993 कर्नाटक 68; राजप्पनअन्य। वी.शंकरन सुधाकरन एयर 1997 केरल 315; कृष्णबाई पांडुरंग सलागरे बनाम सवियाराम गंगाराम कुमिएकर ए. आई. आर. 1927 बॉम्बे 93; अमृतियाल वादिलाल बनाम कांतिलाल लालभाई ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 280; गणेश सखाराम सराफ बनाम नारायण श्रीराम मुलाये ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 484; मणिलाल लल्लूभल पटेल बनाम किकाभाई लालफुभाई ए. आई. आर. 1932 बॉम्बे 482:सोमथ होमप्पा बेनतकर बनाम भीमराव सुब्रव पाटिल 1974 टी. एल. आर. कर्नाटक 1506; जुजोरेसाब बनाम उदाचप्पिया 1984 आई. एल. आर. कर्नाटक 900:बासवत दुंदप्पा आर. वी.सिदलिंगप्पा सिदारद्दी आई. एल. आर. (1986) कर्नाटक

1939; अब्दुल करदार हाजी हिरोली बनाम श्रीमती जुडाह जैकब कोहेन 1969 बी. एल. आर. 749; सकारियाल बनाम पार्वतीबाई (1902) 26 बम 283, अमृतलाल वो।कोंटिफल एयर 1931 बम 280, गणेश बनाम। नारायण एयर 1931 बम 484, दयासभाई बनाम बापालाल (1902) 26 बम 140, फिते!बनाम सुखराम (1899) 1 बम एल. आर. 8534, जमशेदजी बनाम हरि दयाल (1908) 2 बम 181, चोथी तेयवथन बनाम जॉन थॉमस ए. आई. आर. 1997 केर 249, कृष्णबाई बनाम सवियाराम ए. आई. आर. 1927 बम 93, कालपुरी एलम्मा बनाम नेलफुटला वेंकट लक्ष्मी 2008 (72) ऑल इंडिया केस 669; के. उम्मा बनाम टी. के. करप्पन ए. आई. आर. 1989 केर 133-संदर्भित।

" मामला कानून संदर्भ

(1995) उदाहरण 3 एस.सी.सी. 69	संदर्भित	पैरा12
ए.आई.आर. 2000 कर्नाटक 298	संदर्भित	पैरा 13
(1999) 8 एस. सी. सी. 529	निर्दिष्ट	पैरा13
आई.एल.आर. 2006 कर्नाटक 4456	संदर्भित	पैरा 13
1967 एस.सी.आर.93	संदर्भित	पैरा 14
ए.आई.आर. 1993 कर्नाटक 68	संदर्भित	पैरा 15
ए.आई.आर. 1997 केरल 325	संदर्भित	पैरा 15
ए.आई.आर. 1927 बॉम्बे 93	संदर्भित	पैरा 15
ए.आई.आर. 1931 बॉम्बे 280	संदर्भित	पैरा 17
ए.आई.आर. 1931 बॉम्बे 484	संदर्भित	पैरा 17
ए.आई.आर. 1932 बॉम्बे 482	संदर्भित	पैरा 18
1974 आई.एल.आर. कर्नाटक 1506	निर्दिष्ट	पैरा 19

1984 आई.एल.आर. कर्नाटक 900	संदर्भित	पैरा 20
टी.एल.आर. (1986) कर्नाटक 1959	संदर्भित	पैरा 21
1999 (4) कर,एल.जे. 293	अस्वीकृत	पैरा 22
1969 बी.एल.आर. 749	संदर्भित	पैरा 13
(1962) 26 बम 283	संदर्भित	पैरा 23
ए.आई.आर. 1931 बम 280	संदर्भित	पैरा 24
ए.आई.आर. 1931 बम 484	संदर्भित	पैरा 24
{1902) 26 बम 140 को	संदर्भित	पैरा 24
{1899} 1 बम एल. आर. 834	संदर्भित	पैरा 24
(1908) 2 बम 181	संदर्भित	पैरा 24
ए.आई.आर. 1997 केर 249	संदर्भित	पैरा 24
ए.आई.आर. 1927 बम 93	संदर्भित	पैरा 24
2808(72) अखिल भारतीय केस 66 प्रतिशत	संदर्भित	पैरा 24
ए.आई.आर. 1989 केर 1	संदर्भित है	पैरा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3007-3008/2017

उच्च न्यायालय के बैंगलोर में कर्नाटक की रिट याचिका संख्या 16336-16337(GM -सीपीसी) / 2014 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 26.08.2014 से

आर. एस .हेगड़े, श्रीमती फरहत जहां रहमानी, चंद्र प्रकाश, शांति प्रकाश, राजीव सिंह, अधिवक्ता।अपीलकर्ता के लिए।

एस. एन. भट, अधिवक्ता प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश अरुण मिश्रा,जे. द्वारा पारित किया गया :

1. अनुमति स्वीकृत

2. इस मामले में शामिल एकल प्रश्न निर्णय देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की निष्पादन क्षमता है।

3. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, कुंडापुरा के न्यायालय में मूल वाद संख्या 83/2007 के रूप में पंजीकृत याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमा की अनुसूची 'ए' में वर्णित अचल संपत्ति के संबंध में एक मुकदमा दायर किया गया था।अभियोक्ता ने गैर-कृषि/आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि को परिवर्तित कर दिया।अभियोक्ता संपत्ति के कब्जे और आनंद में था और प्रतिअभियोक्ता को इससे कोई सरोकार नहीं था।हालाँकि, उन्होंने लकड़ी की बाड़ को हटाने और नष्ट करने की कोशिश की और अभियोक्ता को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया।इसलिए मुकदमा दायर किया गया था।प्रतिवादी ने दावों का खंडन किया था और तर्क दिया था कि भूमि का कोई विभाजन नहीं था और उसने अपने स्वामित्व और कब्जे का दावा किया था।रूपांतरण भूमि का आदेश भी अवैध था।

4. पंजीकृत विभाजन विलेख के आधार पर पाया गया कि मुकदमा अनुसूची संपत्ति अभियोक्ता को आवंटित की गई थी और उसके कब्जे में थी, प्रतिअभियोक्ता को उसके अपने परिवार में विभाजन पर 1.58 एकड़ आवंटित किया गया था और प्रतिअभियोक्ता ने 1.68 एकड़ भूमि बेच दी थी, हालांकि सर्वेक्षण No.32/5 में उसे आवंटित 10 एकड़ भूमि कुल मिलाकर 1.58 एकड़ थी।मुक़दमे की तारीख को अभियोक्ता को अनुसूची 'ए' संपत्ति के कब्जे में पाया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवादित भूमि में प्रतिवादी का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था। तदनुसार, स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमा राष्ट्रपति के मुकदमे को निर्णय और डिक्री

दिनांक 13.9.2012 के माध्यम से घोषित किया गया था।

5. 13 9.2012 पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का सामना करने के बाद, निर्णय-देनदार दिविरा बोलु की 10.12.2012 पर मृत्यु हो गई।निर्णय-ऋणदाता के उत्तराधिकारियों ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का उल्लंघन करते हुए डिक्री धारक को अनुसूची * ए की संपत्ति से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया।इस प्रकार, डिक्री धारक ने डिक्री पारित होने के दो साल के भीतर निष्पादन याचिका दायर की।निर्णय-ऋणदाता के उत्तराधिकारियों ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि वे स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री से बाध्य नहीं थे।न्याय-देनदार की मृत्यु के साथ डिक्री का बल समाप्त हो गया।डिक्री उनके खिलाफ प्रवर्तन में असमर्थ थी क्योंकि निर्णय देनदार की मृत्यु हो गई थी।रिलायंस को कानूनी उक्ति "एक्शन पर्सनल्स मोरिटुर कम पर्सनैलिटी" पर रखा गया था।निष्पादन अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय-ऋणदाता के उत्तराधिकारी डिक्री से बंधे हैं और उन्हें निर्देश दिया।इस आशय का आश्वासन देना कि वे न्यायालय की डिक्री की अवज्ञा नहीं करेंगे।इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी ने बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे विवादित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री को कानूनी के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है निर्णय-ऋणदाता के उत्तराधिकारी निषेधाज्ञा के रूप में भूमि के साथ यात्रा नहीं करते हैं।

6. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों/निर्णय देनदार के उत्तराधिकारियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री को अप्रवर्तनीय ठहराने में कानूनी रूप से गलती की है। उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखने के लिए धारा 30, धारा 146, आदेश 21 नियम 16, आदेश 21 नियम 32 और धारा 47 सी. पी. सी. पर भरोसा किया है, दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वकील ने यह तर्क देने के लिए कुछ फैसलों का भी

उल्लेख किया है कि स्थायी निषेधाज्ञा का फरमान भूमि के साथ नहीं जाता है।इस प्रकार, यह निर्णय-ऋणदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ अनिर्णायक है,

7. तत्काल मामले में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अभियोक्ता के अधिकार के आधार पर, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री दी गई थी। यह पाया गया कि प्रतिअभियोक्ता ने उस संपत्ति को बेच दिया था जो उसके अपने परिवार के विभाजन में उसके हिस्से में आ गई थी, मुकदमे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिअभियोक्ता विमुकदमाति संपत्ति का मालिक नहीं था और यह अभियोक्ता का था। डिक्री के 24 महीनों के भीतर दायर निष्पादन कार्यवाही में, एक सवाल उठा कि क्या निर्णय देनदार की मृत्यु के बाद, उसके उत्तराधिकारी संपत्ति में हस्तक्षेप शुरू कर सकते हैं और अभियोक्ता उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक और मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य था या स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री को निष्पादित कर सकता था जो निर्णय-देनदार के उत्तराधिकारियों के खिलाफ उसके पक्ष में दी गई थी।

8. सी. पी. सी. की धारा 50 का उल्लेख किया गया है और इसे नीचे निकाला गया हैः

> “50. कानूनी प्रतिनिधि-(1) जहां कोई निर्णय-ऋणी डिक्री के पूरी तरह से संतुष्ट होने से पहले मर जाता है, तो डिक्री का धारक उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसने इसे मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ निष्पादित करने के लिए पारित किया था।
>
> (2) जहां ऐसे कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ डिक्री निष्पादित की जाती है, वह केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक उत्तरदायी होगा जो उसके हाथों में आ गई है और जिसका विधिवत निपटान नहीं किया

गया है; और, ऐसे दायित्व का पता लगाने के उद्देश्य से, डिक्री को निष्पादित प्राथमिकीने वाला न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या डिक्री धारक के संयुक्त आवेदन पर, ऐसे कानूनी प्रतिनिधि को ऐसे खाते पेश प्राथमिकीने के लिए मजबूर प्राथमिकी सकता है जो वह निश्चित समझता है।"

9. सी. पी. सी. की धारा 146 का भी उल्लेख किया गया है और इसे नीचे दिया गया है।

"146. प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही-इस संहिता या तत्काल लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, तो कार्यवाही की जा सकती है या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ आवेदन किया जा सकता है।"

10. सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 16 और आदेश XXI नियम 32 के प्रावधानों को भी संदर्भित किया गया है और उन्हें नीचे भी निकाला गया हैः

"16. स्थानांतरिती द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री-जहाँ एक डिक्री या, यदि एक डिक्री पारित की गई है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से, किसी के भी हित में में समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित डिक्री में डिक्री धारक लिखित या कानून के संचालन द्वारा, स्थानांतरितीकर्ता आवेदन कर सकता है उस न्यायालय को डिक्री का निष्पादन जिसने इसे पारित किया; और डिक्री को उसी तरीके और विषय में निष्पादित किया जा सकता है समान

शर्तों के लिए जैसे कि आवेदन द्वारा किया गया था ऐसे डिक्री धारकः बशर्ते कि जहां डिक्री, या उपरोक्त ब्याज, समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित किया गया है, वहां ऐसे आवेदन की सूचना स्थानान्तरण और निर्णय-देनदार को दी जाएगी, और डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इसके निष्पादन पर उनकी आपत्तियों (यदि कोई हो) को नहीं सुनता हैः बशर्ते कि, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध धन के भुगतान के लिए एक डिक्री उनमें से एक को हस्तांतरित की गई है, तो इसे दूसरों के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जाएगा।{स्पष्टीकरण।–इस नियम में कुछ भी खंड 146 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा, और संपत्ति में अधिकारों का स्थानांतरितीकर्ता, जो मुकदमा की विषय वस्तु है, लागू हो सकता है। इस नियम द्वारा अपेक्षित डिक्री के पृथक समनुदेशन के बिना डिक्री के निष्पादन के लिए।]"

"32. वैवाहिक अधिकारों की बहाली या निषेधाज्ञा के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री।– (1) जहां उस पक्ष को, जिसके खिलाफ किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए, या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित की गई है, डिक्री का पालन करने का अवसर मिला है और वह जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है।डिक्री को उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के मामले में या सिविल जेल में उसकी नजरबंदी द्वारा दूर के निषेधाज्ञा के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के मामले में या उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा लागू किया जा सकता है।या दोनों से।

(2) जहाँ वह पक्ष जिसके विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन के लिए या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित की गई है, वह एक निगम है, वहाँ निगम की संपत्ति की कुर्की द्वारा या न्यायालय की अनुमति से, निदेशकों या उसके अन्य प्रमुख अधिकारियों की सिविल जेल में निरोध द्वारा, या दोनों कुर्की और कुर्की द्वारा आदेश लागू किए जा सकते हैं। नजरबंदी।

(3) जहां उपनियम (1) या उपनियम (2) के तहत कोई कुर्की [छह महीने के लिए] लागू रही है, यदि निर्णय-देनदार ने डिक्री का पालन नहीं किया है और डिक्री-धारक ने 10 कुर्क की गई संपत्ति को बेच दिया है, तो ऐसी संपत्ति बेची जा सकती है और आय में से न्यायालय डिक्री-धारक को ऐसा मुआवजा दे सकता है जो वह उचित समझे, और निर्णय-देनदार को उसके आवेदन पर शेष राशि (यदि कोई हो) का भुगतान करेगा।

(4) जहां निर्णय-ऋणदाता ने डिक्री का पालन किया है और उसी को निष्पादित करने के लिए सभी लागतों का भुगतान किया है जो वह भुगतान करने के लिए बाध्य है, या जहां कुर्की की तारीख से [छह महीने] के अंत में, संपत्ति बेचने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि कुर्की से इनकार कर दिया गया है, तो कुर्की समाप्त हो जाएगी।

(5) जहां किसी निषेधाज्ञा के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी डिक्री का पालन नहीं किया गया है, वहां न्यायालय, उपरोक्त सभी या किसी भी प्रक्रिया के संबंध में या उसके अतिरिक्त,

निर्देश दे सकता है कि किया जाने वाला कार्य निर्णय-धारक या न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णय-देनदार की कीमत पर जहां तक संभव हो, किया जा सकता है, और जो कार्य किया जा रहा है, उसमें किए गए खर्चों का पता उस तरीके से लगाया जा सकता है जो न्यायालय निर्देश दे और उन्हें इस तरह से वसूल किया जा सकता है जैसे कि वे शामिल थे। आदेश में।"

11. सी. पी. सी. की धारा 50 स्थायी निषेधाज्ञा सहित सभी प्रकार के फरमानों के निष्पादन से संबंधित है।सी. पी. सी. की धारा 146 में यह प्रावधान है कि जहां कोई भी आवेदन जो किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जा सकता है, वह संहिता में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जा सकता है।आदेश 21 नियम 16 एक स्थानांतरिती द्वारा डिक्री के निष्पादन से संबंधित है जिससे हम इस मामले में संबंधित नहीं हैं।आदेश 21 नियम 32 निषेधाज्ञा, वैवाहिक अधिकारों की बहाली और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के निष्पादन का तरीका प्रदान करता है।सी. पी. सी. की धारा 33 जो कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ डिक्री के निष्पादन के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है, को आदेश 21 नियम 32 सी. पी. सी. के साथ पढ़ा जाएगा।

12. सी. पी. सी. की धारा 50 (2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्णय देनदार या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री निष्पादित की जा सकती है।मुत्वकरुप्पा पिलफाई एंड एन बनाम गणेशन (1995) सप्लीमेंट 3 एस. सी. सी. 69 में, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की निष्पादन क्षमता के संबंध में एक सवाल उठा कि अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता-अपीलार्थी को हक्कदार और पुजारी के रूप में उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया था।मुकदमे का फैसला सुनाया गया और यह

मुकदमा गया कि उक्त अधिकार वंशानुगत और आंशिक थे।उपरोक्त आधार पर आदेश पारित किया गया था।अभियोक्ता डिक्री-धारक के उत्तराधिकारी ने आदेश को निष्पादन के लिए रखा था।यह तर्क दिया गया था कि निषेधाज्ञा के लिए डिक्री व्यक्तिगत प्रकृति की थी और इसे केवल डिक्री धारक द्वारा लागू किया जा सकता था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि यदि अभियोक्ता की मृत्यु के साथ यह समाप्त हो जाता है और इसे डिक्री धारक के उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, तो इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

> "1, इस न्यायाधीश-ऋणदाता की अपील मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।अपीलकर्ता प्रत्यर्थी के हित में पूर्ववर्ती द्वारा दायर एक मुकदमे में एक प्रति मुकदमा था जो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलकर्ता को उसके अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकता था।कोटराकुरिची गाँव के दो मंदिरों के हाकदार और पुजारी।मुकदमा भले ही निचली निचली अदालत द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन पहली अपील न्यायालय में खारिज कर दिया गया था।लेकिन न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बहाल कर दिया गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से थाः [प्रतिवादी, उनके कर्मचारी, उनके अभिकर्ता आदि को स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा 1965 मार्गली 30 तारीख (यानी 13 जनवरी, 1965 तक) के अंत तक और भविष्य में हर वैकल्पिक वर्ष में वादी की वादी अनुसूची संपत्ति (यहाँ नीचे वर्णित) के आनंद में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
>
> उच्च न्यायालय का निर्णय 1969 में दिया गया था।

डिक्री धारक की जून 1981 में मृत्यु हो गई।प्रत्यर्थी जो दावा करता है कि 10 मूल वाद में अभियोक्ता का गोद लिया हुआ बेटा है और उसके उत्तराधिकारी ने भी फांसी के लिए आवेदन दायर किया है। 198] खंड 146 और आदेश XX के तहत!सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 16।इसका विभिन्न आधारों पर भूखों द्वारा विरोध किया गया था। आवेदन को अनुमति दी गई जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने पुनरीक्षण दायर किया।निष्पादन कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान, प्रतिवादी ने उपायुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें पूजा करने और दोनों मंदिरों से आय के हिस्से का आनंद लेने के अधिकारों का दावा किया गया।आवेदन को उपायुक्त द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधन में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती, मद्रास के आयुक्त द्वारा आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।1 यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी अपने पूर्ववर्ती के पक्ष में दीवानी अदालत द्वारा दिए गए अधिकारों से बेहतर और अधिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की।दोनों, अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण और प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका का निर्णय एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था, उच्च न्यायालय ने कुछ हद तक छोड़कर, निष्पादन में न्यायिक न्यायालय के आदेश को बनाए रखा।प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

2. डिक्री की प्रकृति पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को

प्रमुख चुनौती।यह दावा किया जाता है कि डिक्री व्यक्तिगत होने के कारण, इसे प्रतिअभियोक्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता था, जिसने मुकदमे में अभियोक्ता के उत्तराधिकारी होने का दावा किया था।प्रस्तुतिकरण किसी भी योग्यता से रहित प्रतीत होता है। मुख्य मुकदमा, जिसमें से ये निष्पादन 7 कार्यवाहियाँ उत्पन्न हुई हैं, में उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिकार वंशानुगत और आंशिक थे।इस निष्कर्ष को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता डिक्री के व्यक्तिगत होने का तर्क कैसे उठा सकता है।इसके अलावा, विचारण निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री, जिसकी प्रति प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रामाणिकता अपीलकर्ता द्वारा विवादित नहीं है, और जो पहले निकाली गई है, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि दी गई निषेधाज्ञा ने ऐसे किसी प्रतिबंध ए को स्पष्ट रूप से बाधित नहीं किया और न ही यह निहित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि यह अभियोक्ता की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है।"

इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति या अधिकार से संबंधित स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री निष्पादित कर सकते हैं जो वंशानुगत और आंशिक है, जब ऐसी स्थिति होती है, तो हमारी राय में, डिक्री धारक के लिए निर्णय-ऋणदाता के हित के उत्तराधिकारी के खिलाफ भी डिक्री निष्पादित करने के लिए खुला होगा।

13. रामचंद्र देशपांडे बनाम लक्ष्मण राव कुलकर्णी ए. आई. आर. 2000 कर्नाटक 298

में, प्रतिवादी को वादी के उपयोग और प्रतिवादी के घर के पिछवाड़े द्वारा से उनके रास्ते के अधिकार के आनंद में बाधा डालने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की निष्पादन क्षमता के संबंध में एक सवाल उठा, और बाद में, सदन था "

निर्णय-देनदार-प्रतिवादी द्वारा बेचा गया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश को स्थानांतरिती कर्ता निर्णय-देनदार के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता था। यह नियम कि निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री एक निर्णय-ऋणदाता से एक खरीदार के खिलाफ लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि निषेधाज्ञा इसके लिए एक मुकदमे में से एक उपाय है, अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए शुद्ध रूप से लागू होता है। पर निर्णय लिया गया।अदालत ने कहा कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ डिक्री के प्रवर्तन को धारा 50 सी. पी. सी. द्वारा बचाया गया था और मुकदमा संपत्ति के खरीदार के खिलाफ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उच्च न्यायालय ने मुथुकरुप्पु पिल्लई और अने बनाम गणेशन (ऊपर) और केनहाइवा लाल बनाम बाबू काम (मृत) मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। विधिक प्रतिनिधि और 4 एन. आर. द्वारा(1993) 8 एससीसी 529। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी डिक्री द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा का उपाय किसी भी वंशानुगत और आंशिक अधिकार के संबंध में है, तो यह किसी पक्ष की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, लेकिन डिक्री धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करता है, क्योंकि इस तरह की डिक्री को मृतक निर्णय-देनदार के हित में उत्तराधिकारी के खिलाफ भी निष्पादित किया जा सकता है, इसी तरह का निर्णय जीएम वेंकटप्पा बनाम अंजनप्पा और अन्र में है। आई. एल. आर. 2006 कर्नाटक 4456, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की अयोग्यता का सवाल उठा।

14. आम तौर पर व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति के साथ मर जाता है लेकिन यह सिद्धांत कार्यों के सीमित प्रकार के कारणों पर लागू होता है।गिरिफानंदिनी-देवी बनाम

बिजेंद्र नारायण चौधरी ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1124 में, इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या संपदाओं के खिलाफ लेखा के लिए डिक्री पारित की जा सकती है, इस उक्ति को "सक्रिय व्यक्तिगत" भी माना। है मोरिटुर कम पर्सनैलिटी 'और यह देखा कि यह अभिधारणा कि व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति के साथ मर जाता है, एक सीमित अनुप्रयोग है।[टी सीमित श्रेणी की कार्रवाइयों में काम करता है, जैसे कि नुकसान, हमला या "अन्य व्यक्तिगत चोटों के लिए कार्रवाई जो पैटी की मृत्यु का कारण नहीं बनती हैं और अन्य कार्रवाइयों में जहां मृत्यु के बाद पक्ष को दी गई राहत का आनंद नहीं लिया जा सकता है या इसे देना निरर्थक होगा।अतः उसके द्वारा प्राप्त संपत्ति के लिए लेखा देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु उसकी संपत्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करती है।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

> “{14) अंत में, यह आग्रह किया गया कि चूंकि प्रतिवादी मोड नारायण और राजबल्लव नारायण की कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय इस मामले में अक्षम था। उनकी संपत्तियों के खिलाफ खाते के लिए एक डिक्री पारित करें। राजबल्लव, जो मुकदमा संख्या 6 था, की मृत्यु निचली अदालत और मोड नारायण, जो प्रति मुकदमा था, के लिए मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान हुई। उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीनता रहने के दौरान मुकदमा में नंबर 1 की मृत्यु हो गई।लेकिन लेखा प्रस्तुत करने का दावा एक व्यक्तिगत दावा नहीं है, समाप्त नहीं किया गया है क्योंकि पक्षकार जो खाते का दावा करता है, वह पक्ष जिसे खाते में बुलाया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।मैकिम "एक्शन पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सनैलिटी" एक व्यक्तिगत क्रिया व्यक्ति के साथ मर जाती है, जिसमें एक है सीमित आवेदन।आई. एल. मानहानि, हमला

या अन्य व्यक्तिगत चोटों के लिए हर्जाने के लिए कार्रवाई जैसी सीमित श्रेणी की कार्रवाइयों को संचालित करता है जो किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनती हैं। पक्षकार, और अन्य कार्यों में जहां पक्षकार की मृत्यु के लिए दी गई राहत का आदेश नहीं दिया जा सकता है या इसे देना निरर्थक होगा, आरोप के लिए कार्रवाई एक कार्रवाई नहीं है। मामूली नुकसान के लिए, और यह गणना किए गए वर्गों के भीतर नहीं आता है, और न ही ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से दावा की गई राहत का मृत्यु के बाद आनंद नहीं लिया जा सकता है, या अनुदान नहीं दिया जा सकता है।

यह अशोभनीय होगा।अतः उसके द्वारा प्राप्त संपत्ति का लेखा देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु उसकी संपत्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करती है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह सवाल निचली अदालत और उच्च न्यायालय में नहीं उठाया गया था।यह केवल तर्क दिया गया था कि क्योंकि अभियोक्ता बिजेंद्र नारायण को अपने हिस्से की भूमि की आय प्राप्त हो रही थी, इसलिए खातों के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था।द हाईःअदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस खाते पर अभियोक्ता के पक्ष में कोई लेखा निर्देशित नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि केवल यह तथ्य कि अभियोक्ता संयुक्त परिवार की संपत्तियों के कुछ हिस्से के मालिक थे। 1941 के बाद से प्रतिवादियों को संभावित रूप से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है, जो संपत्तियों के प्रबंधन के साथ अपने व्यवहार के प्रभारी थे।संयुक्त परिवार की संपत्ति का लेखा प्रस्तुत करने से। अभियोक्ता सितंबर 1941 से संपत्ति और अन्य मेस और निवास में

संयुक्त परिवार से अलग हो गया था, और वह सितंबर 1941 से प्रतिवादियों से खाते का दावा करने का हकदार था, लेकिन पिछले लेन-देन के लिए नहीं।यह तथ्य कि अभियोक्ता के पास कुछ संपत्तियां हैं, निश्चित रूप से खाते को समायोजित करने में ध्यान में रखा जाएगा।"

15. जिन उच्च न्यायालयों के विचारों पर भरोसा किया जाता है, वे मोटे तौर पर डिक्री के निष्पादन के पक्ष में हैं।बेशक यह सही मुकदमेबाजी, दर्ज किए गए निष्कर्षों और दिए गए डिक्री की प्रकृति पर निर्भर करता है।कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश उसके बेटे के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, तो यह स्पष्ट है कि इसी तरह का तर्क अभियोक्ता की मृत्यु के मामले में भी अच्छा होना चाहिए जिसने डिक्री प्राप्त की है। डिक्री-धारक के उत्तराधिकारी के लिए निर्णय-देनदार के खिलाफ निषेधाज्ञा को लागू करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए।इस सिद्धांत पर ऐसी कोई कानूनी बाधा नहीं है कि निषेधाज्ञा भूमि के साथ नहीं चलती है।राजप्पन और ओ. आर. एस. अन्य. मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक और खण्ड पीठ।शंकरन सुधाकरन ए. आई. आर. 1997 केरल 325 ने भी निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा डिक्री के उल्लंघन के सवाल पर विचार किया और यह निर्धारित किया कि उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री निष्पादित की जा सकती है, यह देखा गया कि यदि निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री व्यक्तिगत आज्ञाकारिता को मजबूर करती है, तो इसे उचित मामलों में लागू नहीं किया जाएगा। कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ।हालाँकि, यदि मुकदमा और शिकायत किए गए कार्य की विषय वस्तु दूसरे पक्ष की आसन्न संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर थी, तो निषेधाज्ञा के लिए ऐसी डिक्री न केवल निर्णय-देनदार के खिलाफ बल्कि उन सभी के खिलाफ बाध्यकारी होगी जो उसद्वारा से

दावा करते हैं।स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित की गई थी जिसमें निर्णय-देनदारों को डिक्री में अतिक्रमण करने से रोका गया था।अनुसूची संपत्ति उसकी सीमाओं को नष्ट करने और डिक्री धारक के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से।निर्णय-ऋणदाता के कानूनी प्रतिनिधियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।अदालत ने, हमारी राय में, सही निर्णय दिया कि निष्पादन अदालत निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थायी जंक्शन की डिक्री को निष्पादित कर सकती है।

16. कृष्णबाई पांडुरंग सलागेरे बनाम सेवरम ग्वाइगरम कुमटेकर ए. आई. आर. 1927 बॉम्बे 93 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक निर्णय-ऋणदाता के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, तो यह न केवल कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ, बल्कि स्थानांतरितीकर्ता के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। निष्पादन कार्यवाही।

17. अमृतलाल वादिलाल vv.कमीलाल लालभाई ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 280 में यह देखा गया है कि निषेधाज्ञा का आदेश भूमि के साथ नहीं चलता है और संयुक्त परिवार के जीवित सदस्य के खिलाफ या निर्णय-देनदार से खरीदार के खिलाफ वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 50 सी. पी. सी. के तहत शामिल कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है और इसी तरह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार मूल निर्णय-देनदार से हस्तांतरणकर्ताओं के खिलाफ भी। गणेश सखाराम सराफ बनाम नारायण श्रीराम मुलाये ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 484 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि एक निषेधाज्ञा एक व्यक्तिगत उपचार है और भूमि के साथ नहीं होती है, आमतौर पर एक निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री कर सकती है केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ निष्पादित किया जाएगा जिनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई है और वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित नहीं

किया जा सकता है।यदि कोई निषेधाज्ञा डिक्री धारा 50 सी. पी. सी. में निहित वैधानिक प्रावधान के आधार पर निर्णय-ऋणदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लागू करने में सक्षम है, तो इसे निष्पादित किया जा सकता है। समान रूप से उस बेटे के खिलाफ जो अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है और साथ ही उस बेटे के खिलाफ जो पिता के साथ संयुक्त था और जिसे उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दर्ज किया गया था।यह भी देखा गया कि जहां पिता के खिलाफ एक प्रबंधक और संयुक्त परिवार के प्रतिनिधि के रूप में एक डिक्री पारित की गई थी, उसे संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके बेटे के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता था।

18. मेरियल लालीभाई पटेल बनाम कीकाभाई लल्लूभाई ए. आई. आर. 1932 बॉम्बे 482 में एकल पीठ ने निर्णय दिया है कि जहां पिता के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, बेटे को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा रहा है, और निष्पादन कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आदेश 21, नियम 32 के तहत कार्यवाही करके बेटे के खिलाफ उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सी. पी. सी. की खंड 50 के तहत आदेश लागू किया जा सकता है।

19. सोमनाथ होन्नाप्पा बेन्नाटकर बनाम भीनराव सुब्राव पाटिल 1974 [एल. आर. कर्नाटक 1506] में, अभियोक्ता के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक समझौता डिक्री पारित की गई थी, जिसमें निर्णय-देनदार को अभियोक्ता के कब्जे और मुकदमा संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोका गया था।इसके बाद, अभियोक्ता ने अपनी मुकदमा संपत्ति समनुदेशिती को बेच दी और उसके पक्ष में समझौता आदेश भी सौंपा।समनुदेशकर्ता ने निर्णय देनदार के खिलाफ निष्पादन निकाला।1 यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समझौता डिक्री का समनुदेशिती डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं था।यह भी माना गया कि निषेधाज्ञा के लिए समझौता डिक्री व्यक्तिगत थी

और भूमि के साथ नहीं चलती थी।हालाँकि, यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत नहीं आता था।

20. कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने हुजरेसब बनाम उदाचप्पा 1984 आई. एल. आर. कामटका 900 मामले में यह भी निर्णय दिया है कि सी. पी. सी. की धारा 50 के प्रावधानों के तहत मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि जिनके खिलाफ निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है, उस डिक्री के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।यह भी कहा गया था कि धारा 50 सी. पी. सी. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री और किसी अन्य प्रकृति के डिक्री के बीच कोई अंतर नहीं करती है।उच्च न्यायालय ने श्री सूनावाला द्वारा 1958 संस्करण की 'निष्पादन कार्यवाही' का उल्लेख इस प्रकार किया हैः

“श्री सूनावाला द्वारा निष्पादन कार्यवाही में, 1958 संस्करण, पृष्ठ 386 पर यह कहा गया हैः-

> “निषेधाज्ञा का आदेश भूमि के साथ नहीं चलता है और प्रतिवादी से संपत्ति के खरीदार के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।लेकिन इसे मृतक जे के कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ लागू किया जा सकता है।.अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त की, जिसमें प्रतिअभियोक्ता को उसकी खिड़कियों तक प्रकाश और हवा की पहुंच में बाधा डालने से रोक दिया गया।अभियोक्ता ने फांसी के लिए आवेदन करते हुए प्रार्थना की कि प्रतिअभियोक्ता के घर के उस हिस्से को गिरा दिया जाए जो उसकी खिड़कियों को बाधित करता है।जब यह आवेदन लंबित था तो प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके बेटे और उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड में लाया गया।निचली अदालतों ने निर्देश दिया कि डिक्री को प्रार्थना के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए और

अपीलकर्ता (मृतक प्रतिवादी के बेटे और उत्तराधिकारी) को एक निश्चित समय के भीतर घर के बाधा डालने वाले हिस्से को हटाने का निर्देश दिया।अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि मूल प्रतिवादी की मृत्यु के बाद, उसके बेटे (अपीलकर्ता) के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू नहीं की जा सकी क्योंकि निषेधाज्ञा भूमि के साथ नहीं चलती है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मृतक प्रतिवादी के खिलाफ आदेशित निषेधाज्ञा को उसके बेटे और उसके कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ लागू किया जा सकता है। लेखक ने उसी पृष्ठ पर आगे कहा है-' “लेकिन निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादी से संपत्ति के खरीदार के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है जो उसका कानूनी प्रतिनिधि नहीं है।अभियोक्ता ने एक डिक्री प्राप्त की जिसमें प्रतिअभियोक्ता को कुछ भूमि के अपने उपयोगकर्ता के रूप में प्रतिबंधित किया गया और दंड के लिए आवेदन किया गया।मतलब जब भूमि प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य डिक्री के निष्पादन में बेची गई थी और अदालत की बिक्री में शुद्धिकरणकर्ता ने कब्जा प्राप्त किया था।इसके बाद अभियोक्ता ने आवेदन किया कि खरीदार को निष्पादन कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जाना चाहिए और यह कि निष्पादन उसके साथ-साथ प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ भी जाना चाहिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई आदेश या निष्पादन नहीं किया जा सकता है।यह प्रतिवादी के खिलाफ नहीं चल सकता था क्योंकि भूमि में उसका सारा हित एक डिक्री के निष्पादन में बेचा गया था, और यह एक निषेधाज्ञा विलेख के रूप में खरीदार के खिलाफ नहीं चल सकता था। ज़मीन के

साथ भागो।"

लेखक ने आगे कहा है -

"निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री भूमि के साथ नहीं चलती है और किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में, ऐसी डिक्री एक संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के खिलाफ या जे. डी. से एक खरीदार के खिलाफ लागू नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां जे. डी. के बेटों को धारा 50 के तहत उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो उनके खिलाफ डिक्री निष्पादित की जा सकती है और उसी तरह कानूनी प्रतिनिधियों से हस्तांतरणकर्ताओं के खिलाफ भी, धारा 52, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत। उसी सिद्धांत पर, अर्थात।, यह कि वे धारा 52, टी. पी., अधिनियम के तहत निष्पादन कार्यवाही के परिणाम से बाध्य हैं, उसके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान मूल जे. डी. से हस्तांतरणकर्ताओं को समान रूप से बाध्य माना जा सकता है और निष्पादन में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

लेखक ने पृष्ठ 387 पर आगे कहा है -

> "अभियोक्ता के पक्ष में निषेधाज्ञा के माध्यम से कुछ राहत देने का आदेश पारित किया गया था।फांसी के लिए आवेदन करने से पहले, प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और मृतक जे-डी की दो विधवाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में, निष्पादन में अपील विचाराधीनता रहने के दौरान कानूनी प्रतिनिधियों ने अपनी संपत्ति एक अजनबी को हस्तांतरित कर दी।एक सवाल उठाया गया था कि कानूनी प्रतिनिधियों और उनके स्थानांतरितीआदेश्ता के खिलाफ निष्पादन आगे नहीं बढ़ सकता था,

क्योंकि निषेधाज्ञा के माध्यम से दी गई राहत विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत थी और मूल-जे. डी. की मृत्यु हो जाने के बाद, निषेधाज्ञा लागू नहीं हुई है, यह माना गया था कि मूल रूप से कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ दायर किया गया डार्कहास्ट धारा 50, सी. पी. सी. के तहत क्रम में था, और स्थानांतरितीआदेश्ता के खिलाफ भी अच्छा था क्योंकि न्यायालय - सी के अधिकार के तहत स्थानांतरण नहीं किया गया था और डिक्री के निष्पादन में किसी विवाद की कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान प्रभावी होने के कारण, धारा 32, टीपी अधिनियम के तहत अभियोक्ता के अधिकार को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। (कृष्णबाई-बनाम-सावलतम, एल. एल. आर. 51 बोम। 37:100 एल. सी. 582:एएलआर। (1927) बॉम। 93; एस. सी. ई. भी, 9 बम। एल. आर. 1173; एल. एल. आर. 26 बोन, 140,283.) निषेधाज्ञा एक व्यक्तिगत उपाय है और यह भूमि के साथ नहीं चलता है।अतः निषेधाज्ञा के लिए डिक्री केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ निष्पादित की जा सकती है जिनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की जाती है और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित नहीं की जा सकती है। वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में।यदि एक निषेधाज्ञा डिक्री एक वैधानिक प्रावधान के आधार पर जे. डी. के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लागू होने में सक्षम है धारा 50, सी.पी.सी., इसे उस बेटे के खिलाफ समान रूप से निष्पादित किया जा सकता है जो अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है और साथ ही उस बेटे के खिलाफ भी जो पिता के साथ संयुक्त था और जिसे उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है।

ए.डी.एच. ने प्राप्त स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री जारी करने की मांग की अपने बेटों के खिलाफ एक संयुक्त हिंदू परिवार में पिता के खिलाफ।यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश पिता के खिलाफ एक प्रबंधक और संयुक्त परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पारित किया जा रहा है संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके बेटे के खिलाफ फांसी दी जा सकती हैःकि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का उत्तरजीवी पद ग्रहण करने वाले पुत्र को एक "व्यक्ति" के रूप में माना जाना था जो खंड में परिभाषा के पहले भाग के अर्थ के भीतर एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 2(11), सीपीसी {जोर दिया गया}

21. प्रतिवादी द्वारा बसवंत डुंडप्पा बनाम सिदलिंगप्पा सिदारड्डी टीएलआर (1986) कर्नाटक 1959 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब डिक्री धारक द्वारा निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और इसी तरह के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह बनाए रखने योग्य नहीं था, तो उसी राहत के लिए एक और आवेदन वर्जित है।

22. शिवप्पा बसवंतप्पा देवरावर बनाम बाबाजोन 1999 (4) कर में। एल. जे. 293, प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया, जहां स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, निषेधाज्ञा दी गई थी और पहली अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार रखी गई थी और दूसरी अपील दायर की गई थी और निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधि उसी पर मुकदमा चलाना चाहते थे, एक एकल पीठ ने आवेदन किया उक्ति "एक्टियो पर्सनलिस मैरीटुर सीएन पर्सन" का सिद्धांत और यह स्वीकार करना कि कानूनी प्रतिनिधियों को अपील को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था।हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि एकल पीठ ने कानूनी स्थिति की सही सराहना की है क्योंकि मुकदमा

उपरोक्त निर्णय में शीर्षक पर आधारित था।साथ ही, एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यदि अभियोक्ता द्वारा प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त की गई होती और यदि अभियोक्ता की मृत्यु हो जाती, तो कानूनी प्रतिनिधि निषेधाज्ञा के लाभ के हकदार होते।हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में गलती की है।उक्त उक्ति का कोई अनुप्रयोग नहीं था, इसलिए निर्णय को कानून के सही प्रस्ताव को निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

23. एक अन्य निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है, वह है अब्दुल करदार हेय हिरोड्ल बनाम श्रीमती जुडाह जैकब कोहेन 1969 बी. एल. आर. 749 जिसमें भूमि के साथ चलने वाले समझौतों वाले डिक्री की बहिष्करण के बारे में सवाल उठाया गया था और इसे पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया था, अदालत ने कहा कि यह तीसरे पक्ष और भूमि के खरीदार के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं था।यह सवाल विचार के लिए नहीं उठता है क्योंकि वर्तमान मामला भूमि के खरीदारों द्वारा या उनके खिलाफ हस्तांतरण या निष्पादन का मामला नहीं है।

24, विद्वान लेखक मुल्ला ने सिविल प्रक्रिया संहिता (18 "संस्करण) खंड 1 पर अपनी टिप्पणी में सी. पी. सी. की धारा 50 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है (सुकरलाल बनाम पार्वतीबाई (1902) 26 बम 283, अमृतलाल बनाम कांतिलाल एयर 1931 बम 280, गणेश बनाम नारायण एयर 1931 बम 484, दवासभाई बनाम बापालाल (1902) 26 बम 140, विट्ठल बनाम सोखारम (1899)। बम एल. आर 854, जामसेजी बनाम हरि दयाल (1908) 2 बम 18 प्रतिशत, चोथी थेयाथन बनाम जॉन थॉमस सीएटीआर 1997 केर 249, कृष्णबाई बनाम सेवरम एयर 1927।

“12. निषेधाज्ञा के लिए आदेश।- एक प्रतिवादी के खिलाफ प्राप्त

निषेधाज्ञा, उसे वादी के प्राचीन अधिकारों में बाधा डालने से रोकने के लिए, प्रतिवादी की मृत्यु पर, इस खंड के तहत, उसके बेटे के खिलाफ उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, खंड 21, आर 32 (सकारियाल बनाम पार्वतीबाई, (1902) 26 बम 283 के तहत प्रक्रिया द्वारा लागू किया जा सकता है।

[931 बम 280:(1931) 33 बम एलआर 266।सिविल प्रक्रिया संहिता 1882,5260)।उसी तरह।एक संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक और प्रतिनिधि के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश उसकी मृत्यु के बाद एक बेटे के खिलाफ लागू किया जा सकता है जो संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता है (गणेश बनाम नारायण, ए. आई. आर. 1931 बॉम 484:(1931) 55 बम 709)।लेकिन इस तरह का निषेधाज्ञा इस खंड के तहत टाई के खरीदार के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

एक निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादी से संपत्ति भूमि के साथ नहीं चलती है।डिक्री-धारक का उपाय खरीदार के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए एक नया मुकदमा लाना है (दयासभाई बनाम बपालद, (1902) 26 बम 140; फिथावी. सच्चाराम, (1899) 1 बॉम एल. आर. 854; जीनसेरजी बनाम हेरी दयाल, (1908) 32 बॉम 181), जब डिक्री एक निरोधक है। संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति में चट्टानों को विस्फोट करने से इस निष्कर्ष पर कि इस तरह के विस्फोट से डिक्री धारक की निकटवर्ती संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।जब एक बार आईःडिक्री पारित की जाती है, यह स्पष्ट है कि मुकदमे में प्रतिमुकदमी, निर्णय-देनदार, को अपनी संपत्ति में विस्फोटक कार्रवाई करने से रोक दिया

जाएगा।कहने के लिए कि जब वह दूसरों के स्थान पर, वे विशेष संपत्ति के उपभोग से संबंधित प्रतिबंध से बाध्य नहीं होंगे, जो सार्वजनिक नीति के सिद्धांत का अपमान है कि समान अधिकार और समान संपत्ति के संबंध में कोई दूसरा मुकदमा नहीं होगा।यह कानून की नीति नहीं हो सकती है कि हर बार डिक्री अनुसूची संपत्ति का एक असाइनमेंट होता है।डिक्री-धारक को समनुदेशिती के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर करना चाहिए, ताकि उन्हें संपत्ति के मूल मालिक के खिलाफ डिक्री-धारक द्वारा प्राप्त डिक्री की अवज्ञा करने से रोका जा सके (कोरी थेवाथन बनाम जोलिन थॉमस, ए. आई. आर. 1997 केर 249)।धारा 47 के नोट्स देखें, 'प्रतिनिधि सं। (6)-संपत्ति का खरीदार। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू की जा सकती है जिसने खरीद की है जबकि निष्पादन की कार्यवाही लंबित है, इस सिद्धांत के आधार पर मिस पेंडेंस (कृष्णबाई बनाम सवियाराम, ए. आई. आर. 1927 बम 93: (1927)51 बेम 37)।स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री के निष्पादन में, निर्णय-ऋणदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों का दायित्व हस्तक्षेप की सीमा तक सीमित है जो इस तरह के डिक्री द्वारा से प्रतिबंधित किया गया था।केवल ऐसे कानूनी प्रतिनिधि हैं जो उस आदेश की अवहेलना करते हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है (कलपुरी एलम्मा बनाम नेल्लुतला वेंकट लक्ष्मी, 2008 (72) अखिल भारतीय कैस 669)।"

25. के. उनोना बनाम टीके में। करप्पन ए. आई. आर. 1989 केर 133 केरिया के उच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां एक एकल निर्णय-ऋणदाता के खिलाफ

निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री प्राप्त की जाती है, जो उसे अपनी संपत्ति की सीमा पर बाड़ लगाने में अभियोक्ता को बाधित करने से रोकती है, तो डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है।

26. हमारी सुविचारित राय में वर्तमान मामले में मुकदमे में जिस अधिकार पर निर्णय लिया गया था और जो निष्कर्ष मुकदमा संपत्ति के बारे में निषेधाज्ञा देने के लिए आधार के रूप में दर्ज किए गए हैं, जो वंशानुगत और आंशिक हैं, वे न केवल डिक्री धारकों के कानूनी उत्तराधिकारी के लाभ के लिए सुनिश्चित होंगे, बल्कि निर्णय-ऋणदाता के कानूनी प्रतिनिधियों को भी बाध्य करेंगे।सी. पी. सी. की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि जब कोई निर्णय-देनदार डिक्री के संतुष्ट होने से पहले मर जाता है, तो इसे कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।खंड 50 किसी विशेष प्रकार की डिक्री तक सीमित नहीं है।मृतक निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ डिक्री टॉर निषेधाज्ञा भी लागू की जा सकती है।

इस न्यायालय द्वारा गिरफा नंदिनी देवी बनाम बिफेंद्र नारायण चौधरी (उपरोक्त) में बताए गए मामलों के कुछ वर्ग तक ही सीमित है और जब मुकदमा दायर करने का अधिकार विरासत में मिलता है, तो डिक्री सामान्य रूप से उपशमन करना नहीं होगी और डिक्री-ऑयडर के एल. आर. द्वारा और निर्णय-देनदार या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू की जा सकती है, यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा कि डिक्री धारक को निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ एक बार फिर से मुकदमा करने के लिए कहा जाए जब कारण और निषेधाज्ञा बनी रहे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि निषेधाज्ञा का आदेश आम तौर पर भूमि के साथ नहीं चलता है।वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में में इसे लागू नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, सी. पी. सी. की धारा 30 में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की डिक्री को कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।

27. उचित रूप से, हम अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और मानते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश कि कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा डिक्री का पालन करना करने के लिए एक वचन दिया जाना उचित है, जिसमें विफल रहने पर आदेश XXI नियम 32 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत डिक्री को लागू करने के लिए कानून के अनुसार अनुमेय तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कोई लागत नहीं।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।